

## पेपर - 7: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान

### भाग - II

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें

वर्किंग नोट्स को उत्तर का हिस्सा बनाना चाहिए

सभी प्रश्न कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं, जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा गया हो।

#### प्रश्न 1

एक्स लिमिटेड कपड़ा वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित मदों के डेबिट/क्रेडिट के बाद 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इसका शुद्ध लाभ ₹1,25,00,000 था।

- (i) विज्ञापन व्यय में कंपनी के एक निदेशक की सहयोगी कंपनी को नकद में भुगतान की गई 1.60 लाख रुपये की राशि शामिल है। बाजार में ऐसे व्यय का उचित बाजार मूल्य ₹52,000 है।
- (ii) संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत में मशीनरी के खराब हो चुके हिस्सों को बदलने के लिए ₹1.80 लाख शामिल हैं।
- (iii) कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 तक अपने तैयार स्टॉक के मूल्यांकन में ब्याज लागत को शामिल करती थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने ICAI द्वारा जारी लेखांकन मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया और तैयार स्टॉक के मूल्यांकन में ब्याज लागत को बाहर रखा। इससे चालू वर्ष के मुनाफे में 10.70 लाख रुपये की कमी आयी है।
- (iv) विदेश में व्यावसायिक यात्रा के दौरान एक कार्यकारी श्री क्यू की मृत्यु हो गई और कंपनी ने स्वेच्छा से उनके परिवार को ₹ 2.00 लाख की ग्रेच्युटी का भुगतान किया।
- (v) अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया ₹ 1.80 लाख का पूंजीगत व्यय लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया।
- (vi) वर्ष के दौरान बंद हुई कंपनी की एक इकाई के कर्मचारियों को छुट्टी मुआवजे की राशि ₹ 14 लाख दी गई।

- (vii) ₹4 लाख, एक सहकारी बैंक द्वारा मूलधन में से माफ की गई राशि और ₹1 लाख, बैंक द्वारा ब्याज की बकाया राशि पर, क्रमशः एकमुश्त निपटान में माफ की गई राशि है। चार साल पहले कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त किया गया था।
- (viii) केंद्र सरकार द्वारा धारा 80सीसीडी के तहत अधिसूचित कर्मचारियों की पेंशन योजना के लिए योगदान, कर्मचारियों को देय मूल वेतन और महंगाई भत्ते (सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा) के 12% पर गणना की गई 3 लाख रुपये की राशि।

पेपर 7 के लिए सुझाए गए उत्तर: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो मई 2023 की परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष कर निर्धारण वर्ष 2023-24 है।

- (ix) एक अस्थिर डेरिवेटिव अनुबंध के संबंध में ₹6 लाख की बाजार हानि अंकित। अनुबंध मई, 2023 में ₹1 लाख के लाभ के साथ तय किया गया था।
- (f) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान का प्रावधान ₹4 लाख था। उपदान प्रावधान खाते में डेबिट किया गया वास्तविक उपदान ₹2.75 लाख था। श्री क्यू को भुगतान की गई ग्रेच्युटी को अलग से डेबिट किया जाता है और यहां उल्लिखित ग्रेच्युटी या भुगतान की गई वास्तविक ग्रेच्युटी के प्रावधान में शामिल नहीं किया जाता है।

कंपनी इससे संबंधित निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करती है:

- (i) कंपनी ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से 4 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है जिसमें उसके पास 16% वोटिंग अधिकार हैं। ऋण प्राप्ति की तिथि पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का संचित लाभ ₹1 लाख था।
- (ii) कंपनी ने दिवाली के अवसर पर 28.10.2022 को 5 वितरकों को 60,000 रुपये की लागत वाले आई फोन मोबाइल सेट प्रोत्साहन के रूप में दिए हैं। कंपनी के अकाउंटेंट ने व्यवसाय प्रचार व्यय के रूप में उतनी ही राशि डेबिट कर दी, जो व्यवसाय व्यय था और स्रोत पर कोई कर नहीं काटा।
- (iii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुमोदित चुनावी ट्रस्ट को 3,50,000 रुपये की राशि सीधे ट्रस्ट के खाते में आरटीजीएस द्वारा योगदान दी है।

आपको मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए एक्स लिमिटेड की कुल आय की गणना करने की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 115बीए/115बीबी का विकल्प नहीं चुना है।

(14 अंक)

## उत्तर

निर्धारण वर्ष के लिए एक्स लिमिटेड की कुल आय की गणना 2023-24 2023-24			
	विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹ में)	
I	<p>व्यापार और पेशे से लाभ और मुनाफा</p> <p>लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ</p> <p><b>जोड़ें:</b> डेबिट किए गए मद लेकिन अलग से विचार किए जाने या अस्वीकृत किए जाने के लिए</p> <p>(i) विज्ञापन व्यय का भुगतान ₹ 1,60,000</p> <p>[एक्स लिमिटेड के एक निदेशक की सिस्टर कंपनी धारा 40ए(2) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के अंतर्गत आती है। ₹1,08,000, एक निर्दिष्ट व्यक्ति को अतिरिक्त भुगतान होने के कारण धारा 40ए(2) के तहत अस्वीकार्य है। चूंकि भुगतान नकद में किया गया है और चूंकि शेष राशि ₹ 52,000 ₹ 10,000 से अधिक है, इसलिए इसे धारा 40A(3) के तहत अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>चूंकि ₹ 1,60,000 लाभ-हानि खाते से डेबिट कर दिए गए हैं, उसे वापस जोड़ना होगा।]</p> <p><b>नोट -</b> वैकल्पिक रूप से, ₹1,60,000 की पूरी राशि को धारा 40A(3) के तहत अस्वीकार किया जा सकता है।</p> <p>(ii) संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत</p> <p>[मूर्त अचल संपत्तियों पर आईसीडीएस वी के अनुसार, केवल एक व्यय जो मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों को उसके पहले मूल्यांकन किए गए प्रदर्शन मानक से अधिक बढ़ाता है, उसे वास्तविक लागत में जोड़ा जाना चाहिए। चूंकि घिसे हुए हिस्सों के प्रतिस्थापन पर व्यय से कोई नई संपत्ति अस्तित्व में नहीं आती है, ऐसा प्रतिस्थापन वर्तमान मरम्मत की प्रकृति में है, जो कटौती के</p>	1,60,000	1,25,00,000
		-	

	<p>रूप में स्वीकार्य है। चूँकि इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया गया है, इसलिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p> <p><b>(iii) तैयार स्टॉक के मूल्यांकन में ब्याज लागत</b></p> <p>[एक्स लिमिटेड ने तैयार स्टॉक के मूल्यांकन में ब्याज लागत को बाहर रखा है क्योंकि इसने लेखांकन मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनी लेखांकन नीति को बदल दिया है, जो एक वास्तविक कारण है और भविष्य में इसका लगातार पालन किया जाएगा। स्टॉक के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव, एक वास्तविक कारण होने के कारण, किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त ब्याज लागत को पहले ही बाहर रखा गया है और परिणामस्वरूप लाभ कम हो गया है।]</p> <p><b>(iv) श्री क्यू के परिवार को ग्रेच्युटी का भुगतान</b></p> <p>[व्यावसायिक यात्रा के दौरान किसी कार्यकारी की मृत्यु के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान ₹2.00 लाख कटौती के रूप में स्वीकार्य है।<sup>1</sup> चूँकि इसे पहले ही लाभ और हानि खाते से डेबिट किया जा चुका है, इसलिए आगे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p> <p><b>(v) परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 4/5 पूंजीगत व्यय</b></p> <p>[कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया पूंजीगत व्यय धारा 36(1)(ix) के पहले प्रावधान के अनुसार 5 साल की</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>1,44,000</p>	
--	---	-----------------------------------	--

<sup>1</sup> सीआईटी बनाम लक्ष्मी सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लिमिटेड (1976) 104 आईटीआर 711 (गुजरात)

<p>अवधि में कटौती योग्य है। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संबंध में चालू वर्ष में केवल ₹36,000 की कटौती योग्य है। चूंकि ₹ 1,80,000 लाभ और हानि खाते से डेबिट कर दिए गए हैं, ₹ 1,44,000, जो कि पूंजीगत व्यय का 4/5वां हिस्सा है, को वापस जोड़ा जाना है।]</p>		
<p><b>(vi) इकाई बंद होने पर कर्मचारियों को छूटनी मुआवजा</b> [कंपनी की किसी एक इकाई के बंद होने के समय कर्मचारियों को दिया गया छूटनी मुआवजा कटौती के रूप में स्वीकार्य है।<sup>2</sup> चूंकि इसे पहले ही लाभ और हानि खाते से डेबिट कर दिया गया है, इसलिए आगे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p>	-	
<p><b>(viii) एनपीएस में वेतन के 10% से अधिक का योगदान अस्वीकृत</b> [वेतन के 10% की सीमा तक योगदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता, यदि यह सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन का हिस्सा है) धारा 36(1)(iv) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है। इस मामले में, 2%, जो 10% से अधिक है, उदाहरण के लिए, ₹3,00,000 x 2/12, अस्वीकार कर दिया जाएगा।]</p>	50,000	
<p><b>(ix) बाजार घाटे के लिए चिह्नित</b> [आईसीडीएस के अनुसार गणना के अनुसार बाजार हानि या अन्य अपेक्षित हानि को धारा 36(1)(xviii) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। आईसीडीएस I के अनुसार, चिह्नित बाजार घाटे को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि ऐसे नुकसान की पहचान किसी अन्य आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार न हो। एक अस्थिर</p>	6,00,000	

<sup>2</sup> सीआईटी बनाम जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड (2005) 145 टैक्समैन 591 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

<p>डेरिवेटिव अनुबंध के संबंध में बाजार में चिह्नित हानि कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। चूँकि इस तरह के नुकसान को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है, इसलिए व्यावसायिक आय की गणना के लिए उन्हें वापस जोड़ा जाना चाहिए।]</p>		
<p>(x) ग्रेच्युटी का प्रावधान [धारा 40A(7) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए ₹4 लाख का प्रावधान कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, भुगतान किए गए ₹2.75 लाख का वास्तविक उपदान कटौती के रूप में स्वीकार्य है। इसलिए, अंतर को वापस जोड़ना होगा]</p>	<p>1,25,000</p>	
<p>A(ii) स्रोत पर कर कटौती किए बिना वितरक को प्रोत्साहन [30% x ₹60,000 x 5] [वितरकों को मोबाइल फोन एक अनुलाभ या लाभ है जो वितरकों को प्रदान किया जाता है और एक्स लिमिटेड ऐसे लाभ या अनुलाभ पर धारा 194आर के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है। ऐसे लाभ या अनुलाभ पर स्रोत पर कर की कटौती न करने पर धारा 40(ए)(आईए) के तहत 30% की दर से अस्वीकृति आकर्षित होगी]</p>	<p>90,000</p>	
		<p><u>11,69,000</u> 1,36,69,000</p>
<p>घटाएँ: वे वस्तुएँ जो क्रेडिट की गई हैं लेकिन करयोग्य नहीं हैं या किसी अन्य मद के अंतर्गत करयोग्य नहीं हैं</p>		
<p>(vii) बैंक ऋण पर मूलधन की छूट [व्यापारिक गतिविधि के लिए लिए गए ऋण की मूल राशि की छूट, व्यापारिक देनदारी के संबंध में छूट या समाप्ति के माध्यम से एक लाभ है और</p>	<p>-</p>	

	<p>इसलिए, धारा 41(1) के तहत कर योग्य है।<sup>3</sup> चूंकि ऋण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, इसलिए यह मान लेना तर्कसंगत है कि यह व्यापारिक गतिविधि के लिए लिया गया है। चूंकि ऋण माफी पहले ही लाभ और हानि खाते में जमा कर दी गई है, इसलिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p>		
	<p><b>(vii) बैंक ऋण पर ब्याज माफ</b></p> <p>[धारा 43बी के अनुसार, चूंकि ब्याज केवल वास्तविक भुगतान पर ही स्वीकार्य है, ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती किसी भी पिछले वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए, धारा 41(1) को लागू करके ऐसे ब्याज की छूट को कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। चूंकि इस तरह का ब्याज अब लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है, इसलिए व्यावसायिक आय की गणना करते समय इसे घटाया जाना चाहिए।]</p>	1,00,000	
			1,00,000
द्वि	अन्य स्रोतों से आय		1,35,69,000
	<p><b>धारा 2(22)(ई) के तहत माना गया लाभांश</b></p> <p>[एबीसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड को, एक ऐसी कंपनी होने के नाते जिसमें जनता की कोई विशेष रुचि नहीं है, 4 लाख का ऋण, एक शेयरधारक होने के नाते, जिसके पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 16% वोटिंग अधिकार हैं, को लाभांश के रूप में माना जाएगा। संचित लाभ की सीमा तक एक्स लिमिटेड के हाथ यानी,</p>		1,00,000

<sup>3</sup> सॉलिड कंटेनर्स बनाम डीसीआईटी (2009) 308 आईटीआर 417 (बीओएम)

1 लाख]]		
	सम्पूर्ण कुल आय	1,36,69,000
घटाएँ: अध्याय VI-A के तहत कटौती		
धारा 80जीजीबी के तहत [किसी कंपनी द्वारा अनुमोदित चुनावी ट्रस्ट में योगदान कटौती के रूप में स्वीकार्य है, क्योंकि भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है।]		3,50,000
कुल आय		1,33,19,000

## प्रश्न 2

(a) (i) श्री ए, उम्र 34 वर्ष, टीकेएम लिमिटेड में एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:

क्रमांक संख्या	विवरण	राशि ₹ में
1.	सकल वेतन	23,00,000
2.	मोबाइल ट्रेडिंग के नए अंशकालिक व्यवसाय से व्यापार हानि	(4,50,000)
3.	संपत्ति की बिक्री पर अल्पावधि पूंजी हानि (गणना)	(3,60,000)
4.	मिस्टर ए ने 01.04.2022 को 1,000 रुपये प्रति सिक्के के हिसाब से एक आभासी डिजिटल मुद्रा, 1000 बिबकाइन खरीदे, जिसे उन्होंने 15.02.2023 को 1,300 रुपये प्रति सिक्के के हिसाब से बेच दिया। बिबकाइन के हस्तांतरण के लिए कमीशन बिक्री मूल्य का 2% है।	

आपको श्री ए की कुल आय की गणना करने की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आकलन वर्ष 2023-24 के लिए धारा 115बीएसी का विकल्प नहीं चुना है। (4 अंक)

(ii) L, M और N, M/S के तीन साझेदार हैं एल एंड जी एसोसिएट्स, एक साझेदारी फर्म है जिसकी स्थापना 01.04.1995 को हुई थी। 27 जुलाई 2022 को फर्म से सेवानिवृत्त होता है और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, फर्म का व्यवसाय M और N



द्वारा संचालित किया जाएगा। 27 जुलाई 2022 को L के पूंजी खाते का शेष ₹20 लाख है, (संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं है) 2003-04 के बाद किसी भी समय फर्म की पुस्तकों में जब एल एक भागीदार के रूप में फर्म में शामिल हुआ।

फर्म एल को उसका खाता चुकता करने के लिए निम्नलिखित देती है:

(i) ₹ 1,00,000 का नकद भुगतान

(ii) व्यापार में स्टॉक (27 जुलाई 2022 को उचित बाजार मूल्य ₹2,00,000 है)।

यह स्टॉक 15 अप्रैल 2022 को ₹ 1,20,000 में खरीदा गया था।

(iii) कोटा में भूमि का प्लॉट (27 जुलाई 2022 को प्लॉट का उचित बाजार मूल्य ₹17,00,000 है)

प्लॉट का बुक वैल्यू ₹17,00,000 है। इसे 1998-99 के दौरान 60,000 रुपये में हासिल किया गया था। 1 अप्रैल 2001 को प्लॉट का उचित बाजार मूल्य ₹1,10,000 है।

आपको मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए एल एंड जी एसोसिएट्स के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय की गणना करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 331 है और वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए 100 है। (4 अंक)

(b) कोरिया में निगमित कंपनी मैसर्स एबीसी इनकॉर्पोरेट ने गुजरात में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक भारतीय कंपनी XYZ लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। कार्य के दायरे में शामिल हैं -

(i) इलेक्ट्रिकल और नेटवर्किंग कार्य की ड्राइंग और डिजाइन की प्रकृति में अपतटीय सेवाएं; और

(ii) ऐसी मशीनरी की स्थापना के संबंध में तटवर्ती सेवाएं।

कार्य के उपरोक्त दायरे के लिए अपतटीय सेवाओं के लिए ₹3 करोड़ और तटवर्ती सेवाओं के लिए ₹2 करोड़ पर विचार किया गया। विचार-विमर्श इस प्रकार किया गया:

– अपतटीय सेवाओं के संबंध में ₹3 करोड़ का भुगतान 1 जुलाई 2022 को कोरिया में एबीसी के बैंक खाते में किया गया था;

- ऑनशोर सेवाओं के लिए 1 सितंबर, 2022 को 2 करोड़ रुपये के 6% डिबेंचर जारी किए गए थे।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत एम/एस एबीसी इंक के हाथों में उपरोक्त लेनदेन के संबंध में भारत में कर प्रभावों पर चर्चा करें। आपके उत्तर के प्रयोजन के लिए, आप यह मान सकते हैं कि एबीसी इनकॉर्पोरेट की गतिविधियों का भारत में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

कर संधि और डीटीए के प्रावधानों को नजरअंदाज करें. (6 अंक)

उत्तर:

(a) (i) कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए श्री A की कुल आय की गणना

(आयकर अधिनियम, 1961 के नियमित प्रावधानों के तहत)

	विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
I	वेतन		
	सकल वेतन	23,00,000	
	घटाएँ: धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती	<u>50,000</u>	
			22,50,000
द्वितीय	व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ		
	अंशकालिक व्यवसाय से व्यापार हानि	(4,50,000)	
	व्यवसाय से होने वाले नुकसान को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता।		
	आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से किसी भी पूंजीगत लाभ के विरुद्ध व्यावसायिक हानि की भरपाई की अनुमति नहीं है।		
	₹ 4,50,000 की व्यावसायिक हानि		

III.	को आकलन वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाना होगा।		
	<b>पूँजीगत लाभ</b> संपत्ति की बिक्री पर अल्पकालिक पूँजी हानि [अल्पकालिक पूँजी हानि को पूँजीगत लाभ के अलावा किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है। ₹ 3,60,000 की अल्पकालिक पूँजी हानि को आकलन वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाया जाना है]।	(3,60,000)	
IV	यह वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूँजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजन के लिए पात्र नहीं है।		
	<b>पूँजीगत लाभ</b> आभासी डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण से आय [(₹ 1,300 - ₹ 1,000) x 1,000 बिब सिक्के] [अधिग्रहण की लागत के अलावा किसी भी व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं है]		3,00,000
	<b>कुल आय</b>		<b>25,50,000</b>

(ii) आकलन वर्ष 2023-24 के लिए एम/एसएल एंड जी एसोसिएट्स के लिए कर योग्य आय की गणना 2023-24

विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
व्यापार या पेशे के मुनाफ़े और लाभ		

<p><b>एल एंड जी एसोसिएट्स से श्री एल द्वारा व्यापार में स्टॉक की प्राप्ति पर स्थानांतरण माना गया</b></p>		
<p>व्यापार में स्टॉक की प्राप्ति श्री एल एंड जी सहयोगी कंपनियों से एल एंड जी सहयोगी कंपनियों के पुनर्गठन के संबंध में एल एंड जी सहयोगी कंपनियों द्वारा श्री एल को व्यापार में स्टॉक का हस्तांतरण माना जाएगा और इस पर वित्त वर्ष 2022-23 में कर लगाया जाएगा।</p>		
<p>व्यापार में स्टॉक के प्रतिफल का पूरा मूल्य [27.7.2022 को एफएमवी, वह तारीख है जिस दिन व्यापार में स्टॉक श्री एल द्वारा प्राप्त किया गया था]</p>	<p>2,00,000</p>	
<p>घटाएँ: खरीद मूल्य</p>	<p><u>1,20,000</u></p>	
<p><b>व्यापार से लाभ और मुनाफा</b></p>		<p><b>80,000</b></p>
<p><b>पूँजीगत लाभ</b></p>		
<p><b>एल एंड जी सहयोगियों से श्री एल द्वारा भूमि के भूखंड की प्राप्ति पर स्थानांतरण माना गया</b></p>		
<p>एल एंड जी सहयोगियों के पुनर्गठन के संबंध में एल एंड जी सहयोगियों से श्री एल द्वारा भूमि के भूखंड की प्राप्ति को एल एंड जी सहयोगियों द्वारा श्री एल को भूमि के भूखंड का हस्तांतरण माना जाएगा और पिछले वर्ष 2022 में कर योग्य होगा- 23 धारा 9बी के अंतर्गत</p>		
<p>भूमि के भूखंड के प्रतिफल का पूरा मूल्य [27.7.2022 को एफएमवी, वह तारीख जिस दिन श्री एल द्वारा पूँजीगत संपत्ति प्राप्त की जाती है]</p>	<p>17,00,000</p>	

<p>घटाएँ: अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत [1.4.2001 को अधिग्रहण की लागत (₹60,000) और एफएमवी से अधिक (₹1,10,000) यानी, ₹ 1,10,000 x 331/100]</p> <p><b>पूँजीगत लाभ</b></p> <p>एल एंड जी एसोसिएट्स से श्री एल द्वारा नकद और भूमि के प्लॉट की प्राप्ति पर आय मानी गई</p> <p>एल एंड जी सहयोगियों के पुनर्गठन के संबंध में एल एंड जी सहयोगियों से श्री एल द्वारा नकद और भूमि के भूखंड की प्राप्ति पर होने वाले लाभ और लाभ को एल एंड जी सहयोगियों की आय माना जाएगा और पिछले वर्ष 2022 में कर योग्य होगा। -23 धारा 45(4) के तहत</p> <p>नकद भुगतान 1,00,000</p> <p>27.7.2022 को भूमि के भूखंड का एफएमवी <u>17,00,000</u></p> <p><b>18,00,000</b></p>	3,64,100	13,35,900
<p>घटाएँ: पूँजी खाते में शेष राशि [नीचे कार्य नोट देखें]</p> <p>चूंकि, प्रभार्य आय ऋणात्मक है, इसलिए इसे शून्य माना जाएगा</p> <p><b>करयोग्य आय</b></p> <p><b>वर्किंग नोट</b></p> <p>धारा 45(4) के लिए पूँजी खाते में शेष राशि = दिनांक 27.7.2022 को पूँजी शेष, डीमंड ट्रांसफर के कारण उत्पन्न होने वाले बही लाभ/हानि में हिस्सेदारी से बढ़ी/घटी हुई</p> <p>धारा 9बी के तहत डीमंड ट्रांसफर के कारण</p>	19,25,724	-
	(1,25,724)	14,15,900

<p>आयकर के बाद लाभ बुक करें</p> <p>भूमि पर हस्तांतरण पर बुक लाभ = शून्य (₹ 17,00,000 - ₹ 17,00,000)</p> <p>व्यापार में स्टॉक पर स्थानांतरण पर लाभ बुक करें</p> <p>= 80,000 (₹ 2,00,000 - ₹ 1,20,000)</p> <p>धारा 9बी के अनुसार भूमि के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ पर कर = ₹ 13,35,900 x 20.8%</p> <p>= ₹ 2,77,867</p> <p>धारा 9 बी के तहत व्यापार में स्टॉक के हस्तांतरण पर व्यावसायिक आय पर कर = ₹ 80,000 x 31.2% = ₹ 24,960</p> <p>धारा 9बी के तहत स्थानांतरण पर आयकर द्वारा कम किए गए बही-खातों के अनुसार लाभ</p> <p>₹ 80,000 - ₹ 2,77,867 - ₹ 24,960</p> <p>= (₹ 2,22,827)</p> <p>श्री एल के नुकसान का हिस्सा = ₹ 2,22,827/3</p> <p>= ₹ 74,276</p> <p>समायोजन से पहले पूंजी खाता शेष</p> <p>घटाएँ: हानि का हिस्सा</p> <p>27.7.2022 को पूंजी खाते में शेष राशि</p>	<p>20,00,000</p> <p>74,276</p> <p><b>19,25,724</b></p>	
---	--	--

**(b) इलेक्ट्रिकल और नेटवर्किंग कार्य के ड्राइंग और डिजाइन की प्रकृति में अपतटीय सेवाओं के लिए भुगतान:**

इस मामले में, ड्राइंग और डिजाइन की अपतटीय सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में ₹3 करोड़, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की प्रकृति में हैं।<sup>4</sup>

भारत में किए गए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए भारत में निवासी द्वारा देय तकनीकी सेवाओं के शुल्क से आय धारा 9(1)(vii) के तहत भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है, चाहे अनिवासी के पास कोई संपत्ति हो या नहीं। निवास स्थान; या व्यवसाय का स्थान; या भारत में व्यावसायिक संबंध; या अनिवासी ने भारत में सेवाएँ प्रदान की हैं या नहीं।

इसलिए, वर्तमान मामले में, भले ही ड्राइंग और डिजाइन सेवाएँ मेसर्स एबीसी इनकॉर्पोरेट, एक कोरियाई कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली अपतटीय सेवाएँ हैं, XYZ लिमिटेड द्वारा देय ₹3 करोड़ का भुगतान भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा क्योंकि यह है भारत में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए। इसलिए, इस प्रतिफल पर भारत में कर लगाया जाएगा।

**ऐसी मशीनरी की स्थापना के संबंध में तटवर्ती सेवा के लिए भुगतान:**

गुजरात में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए मशीनरी की स्थापना के लिए ऑनशोर सेवाएं यानी तकनीकी सेवाएं प्रदान करने पर विचार करने वाली एक भारतीय कंपनी XYZ लिमिटेड द्वारा जारी किए गए डिबेंचर का मूल्य ₹2 करोड़ है, जो तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की प्रकृति में है। और धारा 9(1)(vii) के तहत मेसर्स एबीसी इनकॉर्पोरेट को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा। इसलिए, यह भारत में कर योग्य है।

**एबीसी लिमिटेड के डिबेंचर पर ब्याज का भुगतान:**

धारा 9(1)(v) के अनुसार, भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा देय ब्याज के माध्यम से आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है, सिवाय इसके कि जहां ब्याज ऋण के लिए देय हो या उधार ली गई धनराशि और उपयोग के लिए हो। भारत के बाहर किए गए व्यवसाय का उद्देश्य और भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना।

---

<sup>4</sup> एईजी एक्टिंजेसलशाफ्ट बनाम सीआईटी (2004) 267 आईटीआर 209 (कर.)

इसलिए, एक भारतीय कंपनी XYZ लिमिटेड के डिबेंचर से ₹7 लाख (₹ 2 करोड़ x 6% x 7/12) की ब्याज आय को अनुभाग के आधार पर मेसर्स एबीसी निगमित के हाथों भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है। 9(1)(वी). इसलिए, यह भारत में कर योग्य है।

### प्रश्न 3

- (a) (i) एक सार्वजनिक कंपनी ने जनता के लाभ के लिए विशेष रूप से एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट ने अन्य बातों के अलावा, ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी के कुछ कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। कर निर्धारण अधिकारी इस लाभ को धारा 13(3) के अंतर्गत शामिल मानता है और ट्रस्ट को दी गई कर छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता है। मूल्यांकन अधिकारी के दृष्टिकोण की सत्यता या अन्यथा पर टिप्पणी करें।

- (ii) लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट एक शैक्षणिक संस्थान चलाता है, जो पूरी तरह से शिक्षा में लगा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2.40 करोड़ की वार्षिक आय प्राप्त हुई। ट्रस्ट केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए मानसिक विकृति से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए एक अस्पताल भी चलाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अस्पताल की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2.50 करोड़ थीं।

लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11, 12 या ऐसे किसी अन्य खंड के तहत कर छूट के लिए पंजीकृत नहीं है। ट्रस्ट के सलाहकार ने उन्हें बताया कि उन्हें किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उन्होंने अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराया हो, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए सलाहकारों के दृष्टिकोण की जांच करें।

(4 x 2 = 8 अंक)

- (b) श्री रिजवी, एक भारतीय निवासी, उम्र 35 वर्ष, वेली ऑयलफील्ड्स, कंट्री एस में प्रति माह AED 9,500 के वेतन पर प्रभारी अधीक्षक के रूप में काम करते हैं। भारत के मुंबई में रहने वाली अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए, वह 1 जुलाई, 2022 को अपने परिवार के साथ स्थानांतरित हो गए और भारत में अपना परामर्श व्यवसाय शुरू किया। भारत में स्थानांतरित होने से पहले, उन्होंने उसी महीने देश में अपनी घर की संपत्ति S@3,250 AED किराए पर दे दी। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रुपये में उनकी आय का विवरण इस प्रकार है:

परामर्श व्यवसाय से लाभ

₹ 8,65,000



कंट्री एस बैंक से सावधि जमा ब्याज	₹ 45,500
एसबीआई, मुंबई से बचत बैंक ब्याज	₹ 18,250
XYZ लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी से लाभांश आय	₹ 7,750

देश S में आयकर की दर 23% है।

पिछले वर्ष के दौरान, श्री रिज़वी ने अपने लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में ₹48,000 और अपने 66 वर्ष के अनिवासी पिता, जो उन पर निर्भर नहीं हैं, के स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में ₹60,000 का भुगतान किया था।

आपको मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए श्री रिज़वी की कुल आय और कर देनदारी की गणना करने की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि भारत ने देश एस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में प्रवेश नहीं किया है और उन्होंने धारा 115बीएसी के प्रावधानों का विकल्प नहीं चुना है। आप इस पर विचार कर सकते हैं (1 एईडी = 23 आईएनआर) (6 अंक)

#### उत्तर

- (a) (i) (1) धारा 11 का लाभ किसी सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट को उपलब्ध नहीं होगा, यदि उसकी आय का कोई हिस्सा धारा 13(3) में किसी व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आता है।
- (2) धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में शामिल हैं -
- ट्रस्ट के लेखक या ट्रस्टी,
  - वह व्यक्ति जिसने प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंत तक ट्रस्ट को ₹50,000 से अधिक का योगदान दिया हो,
  - जहां लेखक या ट्रस्टी या ऊपर उल्लिखित व्यक्ति एक एचयूएफ है, एचयूएफ का सदस्य है
  - ऐसे लेखक, ट्रस्टी या सदस्य का रिश्तेदार
  - व्यक्ति या कोई संस्था जिसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो
- (3) हालाँकि, धारा 13(3) में निषिद्ध व्यक्तियों की सूची में कंपनी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

- (4) इसलिए, ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण के कारण ट्रस्ट को दी गई कर छूट को वापस लेने की मूल्यांकन अधिकारी की प्रस्तावित कार्रवाई गलत है।

**नोट** - धारा 13(3) में लेखक या ट्रस्टी के रिश्तेदार शामिल हैं। हालाँकि, एक नियोक्ता और एक कर्मचारी जैसे अनुबंध के अनुसार संबंध रखने वाले व्यक्ति को रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता है। "रिश्तेदार" का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के साथ जन्म या विवाह से जुड़ा व्यक्ति है। तर्क की यह पंक्ति सीआईटी बनाम टाटा स्टील चैरिटेबल ट्रस्ट (1993) 203 आईटीआर 764 में पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है।

(ii) निम्नलिखित मामलों में अनुमोदन या पंजीकरण की शर्त आवश्यक नहीं है -

- केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान एक शैक्षणिक संस्थान, जिसकी कुल वार्षिक प्राप्तियाँ ₹5 करोड़ से अधिक नहीं हैं, धारा 10(23C)(iiiad) के तहत छूट के लिए पात्र है;
- मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए एक अस्पताल जो पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों के लिए मौजूद है, जिसकी कुल वार्षिक आय ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है, धारा 10 (23 सी) (iii ae) के तहत छूट के लिए पात्र है;

एक शैक्षणिक संस्थान और एक अस्पताल या दोनों को चलाने वाला ट्रस्ट अनुमोदन या पंजीकरण की शर्त के बिना धारा 10(23सी) के तहत छूट के लिए पात्र होगा, यदि शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल से संयुक्त कुल वार्षिक प्राप्तियाँ ₹5 करोड़ से अधिक नहीं हैं।

इस मामले में, लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थान (₹ 2.40 करोड़) और अस्पताल (₹ 2.50 करोड़) से ₹ 4.90 करोड़ की संयुक्त आय, ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं है।

इसलिए, सलाहकार का यह विचार कि ट्रस्ट को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह धारा 11 या 12 या किसी अन्य खंड के तहत पंजीकृत न हो, सही है।

**नोट** - प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से भी दिया जा सकता है -

पहले शासन के तहत छूट धारा 10(23सी) के तहत उपलब्ध है, जहां ट्रस्ट को निर्धारित शर्तों को पूरा करना और कुछ मामलों में प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

धारा 11 के तहत दूसरी व्यवस्था के तहत छूट धारा 12एबी के तहत पंजीकृत और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ट्रस्ट को उपलब्ध है। हालाँकि, ऐसे ट्रस्ट के मामले में जिसकी शिक्षा और परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थापित शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल से संयुक्त प्राप्तियाँ क्रमशः ₹5 करोड़ से अधिक नहीं हैं, न तो प्रधान आयुक्त / आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता है और न ही पंजीकरण की आवश्यकता है।

इसलिए, सलाहकार का यह विचार कि ट्रस्ट को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह धारा 11 या 12 या किसी अन्य खंड के तहत पंजीकृत न हो, सही है।

**(b) आकलन वर्ष 2023-24 के लिए श्री रिज़वी की कुल आय और कर देनदारी की गणना**

विवरण (ब्यौरा)	₹	₹
<b>वेतन</b>		
वेली ऑयलफील्ड्स, देश एस से वेतन आय (9500 एईडी x 3 x ₹23)	6,55,500	
घटाएँ: मानक कटौती	50,000	
		6,05,500
<b>मकान सम्पत्ति से आय</b>		
देश एस में गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य (3,250 एईडी x ₹23 x 9 महीने)	6,72,750	
घटाएँ: धारा 24(ए) के तहत वार्षिक मूल्य का 30% कटौती	2,01,825	
		4,70,925
<b>व्यवसाय या पेशे से होने लाभ और मुनाफे</b>		
भारत में कंसल्टेंसी व्यवसाय से लाभ		8,65,000
<b>अन्य स्रोतों से आय</b>		

कंट्री एस बैंक से सावधि जमा ब्याज	45,500	
एसबीआई मुंबई से बचत बैंक ब्याज	18,250	
XYZ लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी से लाभांश आय	7,750	71,500
<b>सकल कुल आय</b>		<b>20,12,925</b>
<b>घटाएँ: अध्याय VI-A के तहत कटौतियाँ</b>		
<b>धारा 80D के तहत</b>		
स्वयं के लिए मेडिकलेम प्रीमियम ₹ 48,000 तक 25,000 सीमित		
पिता के लिए मेडिकलेम प्रीमियम ₹60,000 तक 25,000 सीमित (चूंकि पिता अनिवासी हैं, भले ही उनकी उम्र 66 वर्ष है)		
	50,000	
<b>धारा 80TTA के तहत</b>		
बचत बैंक खाते पर ब्याज ₹18,250 तक सीमित है	10,000	
		60,000
<b>कुल आय</b>		<b>19,52,925</b>
<b>कुल आय (पूर्णांक में)</b>		<b>19,52,930</b>
<b>कर-देयता ₹ 19,52,930</b>		
कुल आय पर कर [₹ 9,52,930 का 30% + ₹ 1,12,500]		3,98,379
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%		15,935
		4,14,314
<b>घटाएँ: धारा 91 के तहत कटौती (नीचे वर्किंग नोट देखें)</b>		<b>2,38,016</b>
<b>शुद्ध कर देयता</b>		<b>1,76,298</b>
<b>शुद्ध कर देयता (पूर्णांक)</b>		<b>1,76,300</b>

वर्किंग नोट - धारा 91 के तहत कटौती की गणना	
विवरण (ब्यौरा)	₹
<b>दोगुनी कर आय</b>	
वेतन	6,05,500
मकान सम्पत्ति से आय	4,70,925
देश एस में एफडी ब्याज	<u>45,500</u>
	<b><u>11,21,925</u></b>
कर की भारतीय दर = $4,14,314/19,52,930 \times 100 = 21.215\%$	
देश एस में कर की दर = 23%	
उपरोक्त में से निचला = 21.215%	
<b>धारा 91 के तहत कटौती [21.215% x ₹11,21,925]</b>	<b>2,38,016</b>
<b>नोट - प्रश्न में उल्लेख किया गया है कि श्री रिज़वी देश एस में काम करने वाले एक भारतीय निवासी हैं। इसमें दिए गए तथ्य धारा 91 के प्रावधानों के आवेदन का परीक्षण करने के इरादे को दर्शाते हैं। तदनुसार, श्री रिज़वी को निवासी एवं सामान्य निवासी मानकर मुख्य समाधान निकाला गया है।</b>	

#### वैकल्पिक समाधान

प्रश्न में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री रिज़वी जो देश एस में रहते थे और वहां रोजगार में थे, 1 जुलाई, 2022 को अपने परिवार के साथ भारत चले गए और यहां अपना परामर्श व्यवसाय शुरू किया। पहले के वर्षों में उनके भारत में रहने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। वह पिछले वर्ष 2022-23 का निवासी है क्योंकि इस वर्ष उसके प्रवास की अवधि 182 दिन या उससे अधिक है। हालाँकि, चूँकि वह अब तक देश एस में सामान्य रूप से रह रहा है और केवल 1 जुलाई, 2022 को भारत में स्थानांतरित हुआ है, वह मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए भारत का निवासी होगा लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं होगा, इस स्थिति में, द्वारा अर्जित आय पिछले वर्ष 2022-23 में देश एस में उस पर भारत में कर नहीं लगेगा। तदनुसार, इस आधार पर, नीचे एक वैकल्पिक समाधान निकाला गया है -

**आकलन वर्ष 2023-24 के लिए श्री रिज़वी की कुल आय और कर देनदारी की गणना**

विवरण (ब्यौरा)		₹
<b>वेतन से आय</b>		
वेली ऑयलफील्ड्स कंटी एस से वेतन आय (कर योग्य नहीं, क्योंकि आय भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है। चूँकि सेवाएँ भारत के बाहर प्रदान की जाती हैं, इसलिए ऐसी आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जाता है)		-
<b>माकन संपत्ति से आय</b>		
देश एस में गृह संपत्ति से आय (भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय कर योग्य नहीं है क्योंकि श्री रिज़वी एक आरएनओआर हैं)		-
<b>व्यवसाय या पेशे से होने लाभ और मुनाफे</b>	₹	₹
कंसल्टेंसी व्यवसाय से लाभ		8,65,000
<b>अन्य स्रोतों से आय</b>		
देश एस के बैंक से सावधि जमा ब्याज (भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय कर योग्य नहीं है क्योंकि श्री रिज़वी एक आरएनओआर हैं)		-
एसबीआई मुंबई से बचत बैंक ब्याज	18,250	
XYZ लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी से लाभांश आय	7,750	
		<u>26,000</u>
<b>सकल कुल आय</b>		<b>8,91,000</b>
<b>घटाएँ: अध्याय VI-A के तहत कटौतियाँ</b>		
<b>धारा 80D के तहत</b>		
स्वयं के लिए मेडिकलेम प्रीमियम ₹48,000 से ₹ 25,000 तक सीमित	₹ 25,000	
पिता के लिए मेडिकलेम प्रीमियम 60,000 से ₹ 25,000 तक सीमित	₹ 25,000	
(चूँकि पिता अनिवासी हैं, भले ही उनकी उम्र 66 वर्ष है)		

	50,000	
धारा 80TTA के तहत		
बचत बैंक खाते पर ब्याज ₹18,250 तक सीमित है	<u>10,000</u>	<u>60,000</u>
कुल आय		<b><u>8,31,000</u></b>
कर-देयता ₹8,31,000		
कुल आय पर कर [₹ 3,31,000 का 20% + ₹ 12,500]		78,700
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%		<u>3,148</u>
कर देयता		<u>81,848</u>
कर देयता (राउंड ऑफ)		<b>81,850</b>

नोट - इस आधार पर प्रश्न हल करते समय कि श्री रिज़वी एक आरएनओआर हैं, यह माना जा सकता है कि देश एस में गृह संपत्ति से आय या देश एस के बैंक से एफडी ब्याज या दोनों भारत में प्राप्त होते हैं, क्योंकि धारा के तहत कटौती का प्रभाव 91 केवल तभी दिया जा सकता है जब ऐसी धारणा(ओं) बनाई गई हो। दोगुनी कर वाली आय, धारा 91 के तहत कटौती और शुद्ध कर देनदारी के आंकड़े अनुमान के आधार पर भिन्न होंगे।

#### प्रश्न 4

- (a) (i) पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री ए ने अपनी विनिर्माण इकाई के उद्देश्य के लिए श्री बी से ₹ 55 लाख का स्क्रेप खरीदा। श्री ए ने श्री बी को एक प्रमाण पत्र भी दिया कि स्क्रेप का उपयोग श्री ए द्वारा की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। श्री ए ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान श्री बी को ₹ 45 लाख का भुगतान किया। मान लें कि श्री ए और श्री बी दोनों का कारोबार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 10 करोड़ से अधिक है। उपरोक्त मामले में टीडीएस/टीसीएस निहितार्थ पर टिप्पणी करें।(3 अंक)
- (ii) श्री पी अपने विभिन्न ग्राहकों को तकनीकी परामर्श प्रदान करते हैं जो अधिनियम की धारा 194-जे के तहत कर काटते हैं। श्री पी कंसल्टेंसी से अपनी प्राप्तियों के संबंध में टीडीएस अधिकारी से धारा 197 के तहत कम कर कटौती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते हैं। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री पी को कम कर कटौती प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जिससे उन्हें 1% कर की कटौती के बाद परामर्श

भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिली। श्री पी ने यह प्रमाणपत्र अपने ग्राहक श्री क्यू को भेज दिया और उनसे श्री पी को किए जाने वाले 15 लाख के भुगतान पर 1% की दर से कर काटने के लिए कहा।

श्री क्यू ने आपसे श्री पी को किए जाने वाले भुगतान से कटौती की जाने वाली कर की राशि के बारे में सलाह लेने के लिए संपर्क किया है। पी पिछले दो मूल्यांकन वर्षों के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर रहा है और उसके 26एस में टीडीएस क्रेडिट पिछले दो वर्षों में प्रत्येक में 1 लाख से अधिक है यानी वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23। श्री क्यू को आपकी क्या सलाह होगी? **(3 अंक)**

- (iii) सुश्री रोशनी ने 1.8.2022 को दिल्ली में अपनी घर की संपत्ति सुश्री शालिनी को ₹60 लाख में बेच दी। उसने 1.4.2015 को ₹ 36 लाख में घर की संपत्ति खरीदी है। बिक्री की तारीख यानी 1.8.2022 को संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य ₹82 लाख है।

यह मानते हुए कि रोशनी और शालिनी दोनों निवासी व्यक्ति हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सुश्री शालिनी के हाथों में टीडीएस निहितार्थ निर्धारित करें। **(2 अंक)**

- (b) शाही प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, नवंबर 2013 से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है।

कंपनी उपभोग्य सामग्रियों के निर्माण में लगी हुई है। विनिर्माण पूरी तरह से कच्चे माल पर निर्भर है जो जापान की सुमी कंपनी से आयात किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं:

- (i) शाही प्राइवेट लिमिटेड ने सुमी इनकॉर्पोरेट से 30 करोड़ रुपये का माल आयात किया
- (ii) सुमी ने 10% के मार्क-अप के साथ असंबंधित पार्टियों को समान कच्चे माल की आपूर्ति की, जबकि शाही प्राइवेट लिमिटेड ने 20% के मार्क-अप के साथ अर्जित किया।
- (iii) शाही प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी भुगतान के सुमी इनकॉर्पोरेट के ब्रांड नाम का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और जबकि असंबंधित पार्टियां भारत में ऐसे ब्रांड नाम का उपयोग नहीं कर सकती हैं। ब्रांड वैल्यू की वार्षिक लागत ₹90 लाख है।



(iv) कर निर्धारण अधिकारी ने आर्म लेंथ प्राइस (एएलपी) के निर्धारण के लिए मामले को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) के पास भेज दिया।

आपको निम्नलिखित के उत्तर देने होंगे:

- (a) प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए शाही प्राइवेट लिमिटेड की आय में किए जाने वाले लेनदेन और समायोजन की अनुमानित कीमत की गणना करें।
- (b) यदि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) ने शाही प्राइवेट लिमिटेड की आय में 2 करोड़ रुपये की वृद्धि की थी, तो क्या आय की वह बढ़ी हुई राशि धारा 10एए के तहत कटौती के लिए पात्र होगी?
- (c) क्या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) की रिपोर्ट के आधार पर शाही प्राइवेट लिमिटेड आय की कम रिपोर्टिंग के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगी? (6 अंक)

### उत्तर

- (a) (i) धारा 206C1A के अनुसार, श्री B को धारा 206C1A के तहत स्रोत पर कर वसूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री A ने श्री B को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि उससे खरीदा गया स्क्रेप उसके द्वारा संचालित विनिर्माण प्रक्रिया के लिए है और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं है।

हालाँकि, जैसा कि परिपत्र संख्या 13/2021 दिनांक 30.6.2021 और परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 25.11.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है, धारा 194क्यू के तहत टीडीएस धारा 206सी(1ए) के तहत आने वाले ऐसे मामलों में खरीदार के हाथों में आकर्षित किया जाएगा, यदि धारा 194Q के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं।

इस मामले में, खरीदार, श्री ए द्वारा धारा 194Q के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जानी आवश्यक है, क्योंकि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसका टर्नओवर ₹10 करोड़ से अधिक है और उसने मूल्य का सामान खरीदा है या वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऐसे कुल मूल्य ₹50 लाख से अधिक। धारा 194क्यू के तहत टीडीएस ₹50 लाख से अधिक की राशि का 0.1% होगा और इसे भुगतान के समय या निवासी विक्रेता के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, जो भी पहले हो, काटा जाना चाहिए।

इसलिए, वर्तमान मामले में, श्री ए को ₹5,00,000 के 0.1% की दर से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है, जो कि ₹50 लाख से अधिक की राशि है

(₹45,00,000, किया गया भुगतान प्लस ₹10 लाख, राशि है) श्रीमान के खाते में जमा किया गया B).

**टिप्पणियाँ :** यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 206सी(1एच) वहां लागू नहीं होगी जहां धारा 194क्यू लागू है।

- (ii) धारा 194जे के अनुसार, श्री क्यू को श्री पी को तकनीकी परामर्श के लिए भुगतान के संबंध में ₹15 लाख पर स्रोत पर 2% की दर से कर कटौती करने की आवश्यकता है। हालांकि, चूंकि श्री पी ने धारा 197 के तहत कम दर निर्दिष्ट करते हुए जारी कम कर कटौती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमान Q को 1% की दर से, 1% की इतनी कम दर पर कर काटा जाएगा।

हालांकि, धारा 206AB के अनुसार, चूंकि श्री पी ने क्रमशः पिछले वर्ष 2020-21/पिछले वर्ष 2021-22 से संबंधित मूल्यांकन वर्ष 2021-22 / मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय का रिटर्न और टीडीएस का कुल विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। उनके मामले में टीडीएस उक्त पिछले वर्ष में ₹ 1 लाख है, जो कि ₹ 50,000 की सीमा से अधिक है, श्री क्यू को श्री पी को तकनीकी परामर्श के लिए शुल्क के भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है, अन्य बातों के साथ-साथ इससे भी अधिक निम्नलिखित दरें -

- (i) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित दर से दोगुनी दर पर, यानी 4% [धारा 194जे के तहत लागू 2% की दर से दोगुना] [वैकल्पिक रूप से, चूंकि कर धारा 197 के तहत जारी किए गए कम कर कटौती प्रमाण पत्र के अनुसार कटौती योग्य है, 2 की दर उत्तर में % का उल्लेख किया जा सकता है];
- (ii) 5 बजे%

तदनुसार, श्री क्यू को तकनीकी परामर्श शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि, ₹15 लाख पर स्रोत पर 5% की कटौती करने की आवश्यकता है।

**नोट -** उपरोक्त उत्तर इस आधार पर है कि तकनीकी परामर्श से प्राप्तियां तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का प्रतिनिधित्व करती हैं जिस पर 2% टीडीएस लगता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि "तकनीकी परामर्श" भी धारा 194J के तहत "व्यावसायिक सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क हेतु टीडीएस की दर 10% है। यदि तकनीकी परामर्श से प्राप्तियों को पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में माना जाता है, तो धारा 206एबी लागू

करने वाली टीडीएस दर 20% होगी, जो 5% से अधिक या 10% की लागू दर से दोगुनी होगी। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है क्योंकि तकनीकी परामर्श भी धारा 194जे के तहत "व्यावसायिक सेवाओं" की परिभाषा में शामिल है।

- (iii) किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में और हस्तांतरणकर्ता एक निवासी है, जहां प्रतिफल या स्टॉप शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, ₹50 लाख से अधिक है, कर स्रोत पर 1% की दर से कटौती योग्य है।

धारा 194-आईए के अनुसार, सुश्री शालिनी, एक निवासी अंतरिती होने के नाते, दिल्ली में गृह संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में, एक निवासी अंतरणकर्ता सुश्री रोशनी को ₹60 लाख का भुगतान करती हैं, उन्हें ₹82 लाख पर 1% की दर से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है। स्टाम्प शुल्क मूल्य ₹ 82 लाख या प्रतिफल ₹ 60 लाख से अधिक होना।

कटौती की जाने वाली कर = ₹ 82,00,000 x 1% = ₹ 82,000.

- (b) (a) शाही प्राइवेट लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी और जापान की सुमी इंक. को धारा 92ए (2) के अनुसार संबद्ध उद्यम माना जाता है, क्योंकि शाही लिमिटेड का विनिर्माण पूरी तरह से सुमी इंक. से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। इसके अलावा, कच्चे माल की खरीद का लेन-देन 'अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन' के अर्थ में आता है। इसलिए, इस मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधान आकर्षित होंगे।

**आर्म-लेंथ कीमत की गणना और समायोजन करोड़ों में किया जाएगा**

सूमी द्वारा शाही प्राइवेट लिमिटेड से ली गई आयातित वस्तुओं की कीमत 30.00 है

कम : शाही प्राइवेट लिमिटेड से 20% की दर से अर्जित मार्कअप [₹30 करोड़ x 20/120] 5.00

25.00

जोड़ें: अनियंत्रित तुलनीय लेनदेन में अर्जित मार्कअप @10% 2.50

27.50

जोड़ें: ब्रांड मूल्य के आधार पर समायोजन [ब्रांड मूल्य की वार्षिक लागत] 0.90

कच्चे माल की खरीद का उचित मूल्य 28.40

कम : जिस कीमत पर शाही प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुमी इनकॉर्पोरेट से कच्चा माल आयात किया गया था

30.00

शाही प्राइवेट लिमिटेड की आय में समायोजन किया जाएगा

1.60

- (b) शाही प्राइवेट लिमिटेड धारा 10ए के तहत 2 करोड़ रुपये के संबंध में कटौती का दावा नहीं कर सकता है, जो कि धारा 92सी(4) के पहले प्रावधान के आधार पर आय की वह राशि है जिससे टीपीओ द्वारा कुल आय बढ़ाई जाती है।
- (c) नहीं, शाही प्राइवेट लिमिटेड टीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर आय की कम रिपोर्टिंग के लिए दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित बांह की लंबाई की कीमत के अनुरूप किसी भी अतिरिक्त द्वारा दर्शाई गई कम आय की राशि धारा 270ए के तहत कम रिपोर्ट की गई आय के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा, यह मानते हुए कि शाही प्राइवेट लिमिटेड ने धारा 92डी के तहत निर्धारित जानकारी और दस्तावेजों को बनाए रखा है, अध्याय एक्स के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की घोषणा की है और लेनदेन से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा किया है।

#### प्रश्न 5

(a) निम्नलिखित तीन उप-भागों अर्थात् (i), (ii) और (iii) में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए:

- (a) मुद्रा शामिल है
- (b) प्रावधान लागू
- (c) विश्लेषण एवं निष्कर्ष
- (i) मेसर्स रिस्की कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण में लगी हुई है। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, इसने विभिन्न पार्टियों को ₹1.60 करोड़ की राशि का बिना कटौती कर भुगतान किया। हालाँकि, कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि आयकर विभाग के पास जमा करने में विफल रही। कंपनी ने कहा कि उसे वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके देनदारों और आयकर विभाग के पास टैक्स रिफंड के रूप में बड़ी रकम फंसी हुई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वित्तीय संकट के बावजूद, कंपनी ने इस

संबंध में आयकर विभाग से कोई नोटिस प्राप्त करने से पहले, अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज सहित टीडीएस राशि जमा कर दी है। हालाँकि, कर अधिकारी ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ अधिनियम की धारा 276बी के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू की। कंपनी ने इस मामले में सलाह देने के लिए आपसे संपर्क किया है।

- (ii) XYZ लिमिटेड ने स्वीडन स्थित एक अनिवासी कंपनी एम/एस डेल्टा इंक के साथ सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए एक अनुबंध किया। इसने स्रोत पर कर कटौती के बिना सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए अनिवासी कंपनी को भुगतान करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष धारा 195(2) के तहत एक आवेदन दायर किया।

निर्धारिती, एक्सवार्डजेड लिमिटेड ने तर्क दिया कि उक्त अनिवासी कंपनी का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं था और भारत और स्वीडन के बीच डीटीए के संदर्भ में, भारत में उस पर कोई कर नहीं काटा जाना था। एओ ने निर्धारिती के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के लिए मुआवजा रॉयल्टी का गठन करता है और भारत में कराधान के लिए उत्तरदायी होता है और तदनुसार निर्धारिती को उक्त रॉयल्टी भुगतान पर 10% की दर से स्रोत पर कर काटने का निर्देश दिया गया था।

अपील पर, आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती के पक्ष में एक आदेश पारित किया। आगे की अपील पर, ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए किए गए भुगतान रॉयल्टी की प्रकृति के थे और ऐसे भुगतान पर स्रोत पर कर काटा जाना था।

निर्धारिती कंपनी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष धारा 254(2) के तहत सुधार के लिए एक विविध आवेदन दायर किया। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील दायर की थी।

ट्रिब्यूनल ने धारा 254(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और पूरी अपील को गुण-दोष के आधार पर दोबारा सुना और अपने मूल आदेश को वापस ले लिया और निर्धारिती के पक्ष में एक आदेश पारित किया। इसके बाद, निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका भी वापस ले ली गई। क्या ट्रिब्यूनल का अपने मूल आदेश को वापस लेना उचित है? कृपया अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर अपना उत्तर बताएं।

(iii) निर्धारिती, एमपीवी लिमिटेड, अमेरिकी कंपनी, एमपीवी इंक का एक शाखा कार्यालय होने के नाते, भारत में अनुबंध अनुसंधान गतिविधियों और मूल बीजों की खेती में लगा हुआ था। यह अपनी संपूर्ण आय को कृषि आय मानकर छूट का दावा कर रहा था।

वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के लिए जांच मूल्यांकन पर, मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती की पूरी आय को "व्यावसायिक आय" के रूप में माना और निर्धारिती कंपनी को एमपीवी निगमित की स्थायी स्थापना (पीई) के रूप में रखने वाली अनुसंधान गतिविधि से मानी गई आय को जिम्मेदार ठहराया। निर्धारिती कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच डीटीए समझौते के तहत पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (एमएपी) के तहत समाधान के लिए मामले पर विवाद किया। एमएपी का समापन वर्ष 2020 में हुआ। मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया और निर्धारिती द्वारा धारा 220 के तहत ब्याज सहित कर का भुगतान किया गया।

हालाँकि, निर्धारिती ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए धारा 220(2) के तहत ब्याज की राशि पर विवाद किया।

इसके बाद निर्धारिती कंपनी ने धारा 220(2ए) के तहत लगाए गए ब्याज की छूट के लिए धारा 220(2ए) के तहत क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया। कमिशनर ने करदाता का आवेदन खारिज कर दिया।

निर्धारिती कंपनी एमपीवी इंक का एक हिस्सा है, जो एक वैश्विक समूह है, जिसकी 2020 में शुद्ध बिक्री 94,000 करोड़ रुपये और परिचालन लाभ 12,000 करोड़ रुपये था। अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज के रूप में इसके द्वारा भुगतान की गई राशि 2.50 करोड़ थी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के अनुसार, क्या आयकर आयुक्त द्वारा निर्धारिती के दावे को खारिज करना उचित है या नहीं।

(4 x 2 = 8 अंक)

(b) संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनी किवी इनकॉर्पोरेट विश्व स्तर पर मोबाइल फोन के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। यह प्रत्येक मोबाइल फोन को 2,000 अमेरिकी डॉलर में बेचता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक अन्य कंपनी, अल्फा इनकॉर्पोरेट, एक वेबसाइट का मालिक है और उसका प्रबंधन करती है, जो सामान खरीदने और बेचने के लिए बाज़ार के रूप में कार्य करती है और विज्ञापन भी होस्ट करती है। गामा एलएलसी, यूके में निगमित कंपनी, प्रिंटर के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है।

पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, कीवी ने 80,000 मोबाइल फोन बेचे, जो निम्नानुसार हैं-

वह प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से मोबाइल फोन बेचे जाते हैं	वह ग्राहक जिसे मोबाइल फोन बेचे गए हैं	बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या
अल्फा के माध्यम से सम्मिलित करें	वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं	15,000
अल्फा के माध्यम से सम्मिलित करें	वे व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं	25,000
कीवी के माध्यम से अपनी वेबसाइट शामिल करें	वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं	7,000
कीवी के माध्यम से अपनी वेबसाइट शामिल करें	जो व्यक्ति भारत के निवासी नहीं हैं, वे यूके में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं	12,000
कीवी के माध्यम से अमेरिका में फिजिकल स्टोर शामिल है	वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं	21,000
<b>कुल</b>		<b>80,000</b>

गामा एलएलसी ने 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए अल्फा इनकॉर्पोरेट की वेबसाइट पर अपना विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अल्फा इनकॉर्पोरेट के साथ एक अनुबंध किया है। गामा एलएलसी ने भारतीय ग्राहकों के लिए भारत में विज्ञापन होस्ट करने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर और यूके के ग्राहकों के लिए यूके में विज्ञापन होस्ट करने के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। कीवी इनकॉर्पोरेट, अल्फा इनकॉर्पोरेट और गामा एलएलसी का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार उपरोक्त परिदृश्य में भारत के कर निहितार्थों पर चर्चा करें। आप मान सकते हैं कि मोबाइल फोन की बिक्री पूरे वर्ष समान रूप से वितरित की गई और 1 USD की दर ₹80 के बराबर है। (6 अंक)

### उत्तर

- (a) (i) **मुद्दा शामिल है:** विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जहां निर्धारित द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित समय के बाद, लेकिन आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त करने से पहले, धारा 201 (1 ए) के तहत

ब्याज के साथ कर कटौती कर जमा कर दी गई है। और निर्धारिती ने ऐसी देरी के लिए उचित कारण दिखाया है।

**प्रावधान लागू:** धारा 276बी के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाती है, यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान करने में विफल रहता है।

धारा 278ए में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी विफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि इसके लिए उचित कारण था।

**विश्लेषण और निष्कर्ष:** इस मामले में, कंपनी के पास उचित और पर्याप्त कारण है क्योंकि वह देनदारों के साथ बड़ी रकम फंसने और आयकर विभाग के पास रिफंड के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही थी। वित्तीय संकट के बावजूद, कंपनी ने इस संबंध में आयकर विभाग से कोई नोटिस प्राप्त होने से पहले, अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत ब्याज सहित टीडीएस जमा कर दिया है।

चूंकि उसने विभाग से कोई नोटिस प्राप्त होने से पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए ब्याज सहित टीडीएस जमा कर दिया है और जमा करने में इस तरह की देरी के लिए उचित कारण भी दिखाया है, इसलिए कंपनी को टीडीएस जमा करने में देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी और निदेशकों के खिलाफ धारा 276बी के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू करना सही नहीं है।

- (ii) **मुद्दा शामिल है:** विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या धारा 254(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग ट्रिब्यूनल द्वारा किसी आदेश को वापस लेने और संपूर्ण अपील को गुण-दोष के आधार पर दोबारा सुनने के लिए किया जा सकता है।

**प्रावधान लागू:** धारा 254(1) अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील के दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस पर ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार देती है जैसा वह उचित समझे।

धारा 254(2) के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण, रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधारने की दृष्टि से धारा 254(1) के तहत पारित आदेश में संशोधन कर सकता है।

**विश्लेषण और निष्कर्ष:** धारा 254(2) के तहत शक्ति रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती के सुधार तक सीमित है और इसलिए, ट्रिब्यूनल को खुद को उन मापदंडों के भीतर सीमित करना चाहिए।



मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था। धारा 254(2) के तहत आवेदन की अनुमति देते हुए और अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने पूरी अपील को गुण-दोष के आधार पर फिर से सुना था जैसे कि ट्रिब्यूनल आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला कर रहा था। ट्रिब्यूनल द्वारा अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए पारित किया गया बाद का आदेश धारा 254(2) के तहत शक्तियों के दायरे और दायरे से परे था और कानून में मान्य नहीं है।

**नोट - प्रश्न में दिए गए तथ्य रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड/रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (2022) 440 आईटीआर 1 (एससी) के तथ्यों के समान हैं, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उपरोक्त उत्तर उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क पर आधारित है।**

- (iii) **मुद्दा शामिल है:** विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या एमएपी के तहत विवाद समाधान का लंबित रहना धारा 220(2ए) के तहत ब्याज की छूट के लिए वैध आधार है।

**प्रावधान लागू:** धारा 220(2) में मांग की सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में देरी के लिए साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान है।

धारा 220(2ए) धारा 220(2) के तहत देय ब्याज में कटौती या छूट का प्रावधान करती है, यदि, अन्य बातों के साथ, आयुक्त संतुष्ट है कि ऐसी राशि के भुगतान से निर्धारिती को वास्तविक कठिनाई हुई है या होगी।

**विश्लेषण और निष्कर्ष:** केवल किसी प्राधिकारी के समक्ष विवाद उठाना धारा 220(2ए) के तहत ब्याज की छूट का आधार नहीं हो सकता। अन्यथा, प्रत्येक निर्धारिती विवाद उठा सकता है और उसके बाद यह तर्क दे सकता है कि चूंकि मुकदमा प्रामाणिक था, इसलिए कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, इस मामले में, निर्धारिती एक वैश्विक समूह का हिस्सा है जिसकी 2020 में शुद्ध बिक्री 94,000 करोड़ रुपये और परिचालन लाभ 12,000 करोड़ रुपये था। वर्षों की लाभप्रदता की तुलना में, धारा 220(2) के तहत ब्याज के रूप में इसके द्वारा भुगतान की गई राशि केवल 2.50 करोड़ थी। यह तथ्य इस निष्कर्ष में प्रासंगिक है कि ब्याज के भुगतान के कारण निर्धारिती को कोई 'वास्तविक कठिनाई' नहीं हुई है।

इसलिए, आयकर आयुक्त द्वारा निर्धारिती के दावे को खारिज करना उचित है।

**नोट** - प्रश्न में दिए गए तथ्य पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए (भारत शाखा) बनाम सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (2022) 449 आईटीआर 186 के तथ्यों के समान हैं, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उपरोक्त उत्तर उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क पर आधारित है।

**(B) कीवी इंक/अल्फा निगम के हाथों में कर संबंधी निहितार्थ**

(1)	(2)
कीवी निगम द्वारा किया गया लेनदेन	कीवी इनकॉर्पोरेट/अल्फा इनकॉर्पोरेट के हाथों में कर संबंधी निहितार्थ
(i) अल्फा इनकॉर्पोरेट के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को 15,000 मोबाइल फोन की बिक्री	<p>ई-कॉमर्स ऑपरेटर अल्फा इंक को 2% की दर से इक्वलाइजेशन लेवी का भुगतान करना होगा, क्योंकि ई-कॉमर्स आपूर्ति भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, जिसके लिए प्रतिफल ₹2 करोड़ से अधिक है।</p> <p>प्रतिफल = <math>15,000 \times 2,000 \times ₹80 = ₹240</math> करोड़</p> <p>अल्फा इंक द्वारा देय ईएल = <math>2\% \times ₹240</math> करोड़ = ₹4.80 करोड़</p> <p>धारा 10(50) के तहत छूट के कारण कीवी इंक के हाथों में कोई आयकर देनदारी नहीं होगी।</p> <p><b>ध्यान दें</b> - यह दृष्टिकोण इसलिए लिया गया है क्योंकि सकल बिक्री पर ईएल लगाया जाता है, भले ही अल्फा इनकॉर्पोरेट इस मामले में केवल कीवी कॉर्पोरेशन द्वारा फोन की बिक्री की सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कीवी इनकॉर्पोरेट धारा 10(50) के तहत छूट का लाभ उठा सकता है, क्योंकि लेनदेन पहले से ही अल्फा इनकॉर्पोरेट के हाथों में समकारी लेवी के अधीन है।</p> <p>वैकल्पिक रूप से, यह विचार करना संभव है कि धारा 10(50) के तहत छूट कीवी इंक को उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी का भुगतान अल्फा इनकॉर्पोरेट द्वारा किया जाता है। यदि यह विचार लिया जाता है, तो इस लेनदेन के कारण होने वाली आय इसके अधीन होगी। भारत में कीवी निगम की</p>

		महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण कीवी निगम के हाथों में आयकर, जिससे भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए।
(ii)	अल्फा के माध्यम से 25000 मोबाइल फोन की बिक्री उन व्यक्तियों को की गई जो भारत के निवासी नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन में बैठे हैं	भारत के बाहर स्थित गैर-निवासियों को मोबाइल फोन की बिक्री पर अल्फा इनकॉर्पोरेट के हाथों में समकारी लेवी आकर्षित नहीं होती है। कीवी निगम के हाथों में आयकर देनदारी भी लागू नहीं होती है क्योंकि आय भारत के बाहर अर्जित होती है और एक अनिवासी द्वारा भारत के बाहर प्राप्त की जाती है, यानी कीवी निगमित
(iii)	भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कीवी इंक की अपनी वेबसाइट के माध्यम से 7,000 फोन की बिक्री	कीवी इंक के हाथों में 2% की दर से समकारी लेवी लगाई गई है, क्योंकि इससे भारत में रहने वाले व्यक्तियों को ई-कॉमर्स आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके लिए प्रतिफल ₹2 करोड़ से अधिक है। $\text{प्रतिफल} = 7,000 \times 2,000 \times ₹80 = ₹112 \text{ करोड़}$ $\text{अल्फा इंक द्वारा देय ईएल} = 2\% \times ₹240 \text{ करोड़} = ₹4.80 \text{ करोड़}$ धारा 10(50) के तहत छूट के कारण कीवी इंक के हाथों में कोई आयकर देनदारी नहीं होगी।
(iv)	कीवी इंक की अपनी वेबसाइट के माध्यम से उन व्यक्तियों को 12,000 फोन की बिक्री, जो भारत के निवासी नहीं हैं, यूके में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं	भारत के बाहर इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके भारत से बाहर रहने वाले गैर-निवासियों को मोबाइल फोन की बिक्री पर कीवी कंपनी के हाथों में समकारी लेवी लागू नहीं होती है। कीवी निगम के हाथों में आयकर देनदारी भी लागू नहीं होती है क्योंकि आय भारत के बाहर अर्जित होती है और एक अनिवासी द्वारा भारत के बाहर प्राप्त की जाती है, यानी कीवी निगमित
(v)	अमेरिका में कीवी के फिजिकल स्टोर के माध्यम से भारत में	चूंकि बिक्री भारत के बाहर हुई है, इसलिए कीवी इनकॉर्पोरेट के हाथों कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी

	रहने वाले व्यक्तियों को 21,000 फोन की बिक्री।	
--	---	--

**भारतीय ग्राहकों के लिए विज्ञापन की मेजबानी के लिए अल्फा निगम द्वारा गामा एलएलसी से 50,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए**

एक अनिवासी गामा कॉरपोरेशन द्वारा अल्फा इंक को भुगतान की गई 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि, एक अन्य अनिवासी, एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर होने के नाते, अल्फा इंक के हाथों में 2% की दर से ईएल के अधीन होगी, क्योंकि वही इसके लिए है भारत में विज्ञापन की मेजबानी करना एक निर्दिष्ट परिस्थिति है।

अल्फा द्वारा देय ईएल = 2% x USD 50,000 x ₹80 = ₹80,000।

**यूके के ग्राहकों के लिए यूके में विज्ञापन होस्ट करने के लिए अल्फा निगम द्वारा गामा एलएलसी से 20,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए**

भुगतान की गई 20,000 अमेरिकी डॉलर की राशि के संबंध में कोई समकारी लेवी नहीं लगती है क्योंकि यह भारतीय ग्राहकों को लक्षित करने के लिए नहीं है।

कोई आयकर देनदारी लागू नहीं होती क्योंकि भारत में अल्फा इंकॉर्पोरेट के लिए कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं होती या अर्जित या उत्पन्न होती नहीं मानी जाती है।

**नोट** - प्रश्न में उम्मीदवारों को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार दिए गए परिदृश्य में भारत कर निहितार्थ पर चर्चा करने की आवश्यकता है। चूंकि उसमें सूचीबद्ध अधिकांश लेन-देन एक अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से होता है, इसलिए पहले समकारी लेवी के निहितार्थों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। यदि लेनदेन समकारी लेवी के अधीन है, तो, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(50) के तहत छूट दी जाएगी। अन्यथा, इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या लेन-देन से होने वाली आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 के तहत आयकर की प्रभार्यता को आकर्षित करने के लिए भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है। ऊपर दिया गया मुख्य उत्तर इसी तर्ज पर तैयार किया गया है।

हालाँकि, प्रश्न 5 (बी) में "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार" के विशिष्ट संदर्भ के कारण, समान लेवी के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए एक वैकल्पिक उत्तर नीचे दिया गया है, क्योंकि लेवी स्वयं के अध्याय VIII के माध्यम से है वित्त अधिनियम, 2016 और आयकर अधिनियम, 1961 के माध्यम से नहीं:

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर संबंधी निहितार्थ, समकारी लेवी की अनदेखी		
(1)		(2)
कीवी निगम द्वारा किया गया लेनदेन		कीवी के हाथों में कर संबंधी निहितार्थ शामिल हैं
(i)	भारत में रहने वाले व्यक्तियों को अल्फा इनकॉर्पोरेट के माध्यम से 2,000 अमेरिकी डॉलर की दर से 15,000 मोबाइल फोन की बिक्री	भारत में कीवी इनकॉर्पोरेट की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति इन मामलों (i) और (iii) में उल्लिखित लेन-देन) में उत्पन्न होती है क्योंकि ये लेन-देन भारत में उन व्यक्तियों के साथ हैं जिनके संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में कुल भुगतान ₹ 2 करोड़ रुपये से अधिक है।
(iii)	भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कीवी इंक की अपनी वेबसाइट के माध्यम से 2,000 अमेरिकी डॉलर की दर से 7,000 फोन की बिक्री	इसलिए, व्यापार कनेक्शन का गठन किया गया है और ऐसे लेनदेन के कारण होने वाली आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा और कीवी निगम के हाथों आयकर के लिए प्रभावी होगा
(ii)	अल्फा के माध्यम से 25000 मोबाइल फोन की बिक्री उन व्यक्तियों को की गई जो भारत के निवासी नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन में बैठे हैं	(ii) और (iv) में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में कीवी निगमित के हाथों आयकर देनदारी आकर्षित नहीं होती है क्योंकि आय भारत के बाहर अर्जित होती है और एक अनिवासी द्वारा भारत के बाहर प्राप्त की जाती है, अर्थात्, कीवी निगमित
(iv)	कीवी इंक की अपनी वेबसाइट के माध्यम से उन व्यक्तियों को 12,000 फोन की बिक्री, जो भारत के निवासी नहीं हैं, यूके में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं	इस मामले में कोई व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, और इसलिए, कीवी निगम के हाथों भारत में कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी गई है
(v)	अमेरिका में कीवी के फिजिकल स्टोर के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को 21,000 फोन की बिक्री।	चूंकि बिक्री भारत के बाहर हुई है, इसलिए कीवी इनकॉर्पोरेट के हाथों कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाएगी

<b>भारतीय ग्राहकों के लिए भारत में विज्ञापन होस्ट करने के लिए अल्फा निगम द्वारा गामा एलएलसी से 50,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए</b>
भारत में किए गए परिचालनों से होने वाली आय, जिसे भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है, में विज्ञापन से होने वाली आय शामिल होगी जो भारत में रहने वाले ग्राहकों को लक्षित करती है। तदनुसार, भारतीय ग्राहकों के लिए भारत में विज्ञापन होस्ट करने के लिए अल्फा इंकॉर्पोरेटड द्वारा गामा एलएलसी से प्राप्त 50,000 अमेरिकी डॉलर की आय अल्फा इंकॉर्पोरेटड के हाथों आयकर के दायरे में आएगी।
<b>यूके के ग्राहकों के लिए यूके में विज्ञापन होस्ट करने के लिए अल्फा निगम द्वारा गामा एलएलसी से 20,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए</b>
कोई आयकर देनदारी लागू नहीं होती क्योंकि भारत में अल्फा इंकॉर्पोरेटड के लिए कोई आय अर्जित या उत्पन्न नहीं होती या अर्जित या उत्पन्न होती नहीं मानी जाती है।

**प्रश्न 6**

- (a) (i) टिप्पणी करें कि क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए निम्नलिखित लेनदेन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के तहत आवश्यक वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट योग्य खाते के विवरण के तहत रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। कृपया अपना उत्तर उपयुक्त कारणों और रिपोर्टिंग व्यक्ति की श्रेणी सहित दें।
- (a) श्री ए ने भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर के अपने वर्तमान खाते से प्रत्येक 3 लाख के पांच बैंक ड्राफ्ट खरीदे;
- (b) सुश्री क्यू ने केनरा बैंक, जयपुर में दो सावधि जमाएं कीं - (ए) 07-08-2022 को किया गया 7 लाख का सावधि जमा और (बी) 1.1.2022 को मूल रूप से किए गए 5 लाख के सावधि जमा का नवीनीकरण और नवीनीकरण किया गया 1.1.2023;
- (c) सुश्री सी ने क्रेडिट कार्ड भुगतान के संबंध में निम्नलिखित भुगतान किए-

• अप्रैल से जुलाई, 2022 के महीनों के लिए	-	प्रत्येक माह के लिए ₹19,500 नकद
• अगस्त से दिसंबर, 2022 के महीनों के लिए	-	प्रत्येक माह के लिए ₹59,500, बैंक खाते के माध्यम से
• जनवरी से मार्च, 2023 के महीनों के लिए	-	प्रत्येक माह के लिए ₹13,300 नकद

- (d) मिस्टर ज़ेड ने अपनी शादी के अवसर पर मेसर्स अरोड़ा डिज़ाइनर्स से ₹ 2 लाख नकद के कपड़े खरीदे। मेसर्स अरोड़ा डिज़ाइनर्स आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के तहत ऑडिट के लिए उत्तरदायी है। (4 अंक)
- (ii) कर कानूनों के मामले में वरीयता का सिद्धांत लागू होगा। प्राथमिकता के सिद्धांत के प्रकाश में, अपने उत्तरों के कारणों सहित निम्नलिखित कथनों की सत्यता या अन्यथा पर टिप्पणी करें:
- (a) सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात डिसेंडी (किसी मामले को तय करने का औचित्य) सभी निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर बिल्कुल बाध्यकारी है। हालाँकि, निचली अदालतें, न्यायाधिकरण और प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के ओबिटर डिक्टा (अतिरिक्त टिप्पणियाँ या वैसे कही गई बातें) से बंधे नहीं हैं।
- (b) जहाँ सर्वोच्च न्यायालय की समान शक्ति वाली दो पीठों के दो असंगत निर्णय हों, वहाँ विषय पर अधिक विस्तृत चर्चा वाला निर्णय मान्य होगा।
- (c) निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से बंधी होती हैं। इस सिद्धांत का एकमात्र अपवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हैं (यानी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख किए बिना)।
- (d) निचले अधिकारी उच्च न्यायालय के निर्णय से विचलित हो सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में वे कार्य करते हैं, केवल उस स्थिति में जब विभाग ने उक्त निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गया है। (4 अंक)
- (b) (i) वियना के तहत प्रदान की गई कर संधि की "व्याख्या का सामान्य नियम" क्या है? संधियों के कानून पर कन्वेंशन? (2 अंक)
- (ii) संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन में प्रतिपादित सिद्धांतों के मद्देनजर निम्नलिखित शब्दों "पैक्टा सनट सर्वडा (अच्छे विश्वास में)" की व्याख्या करें। (1 अंक)
- (iii) ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल के तहत मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 25 के अनुसार "पारस्परिक समझौता प्रक्रिया" शब्द की व्याख्या करें। (3 अंक)

### उत्तर

- (a) (i) (a) भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर को श्री सिंह द्वारा खरीदे गए बैंक ड्राफ्ट के मूल्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ए, भले ही ऐसे बैंक ड्राफ्ट का कुल

मूल्य, अर्थात् 15 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 10 लाख रुपये से अधिक हो, क्योंकि ऐसे बैंक ड्राफ्ट उसके वर्तमान ए/सी से खरीदे जाते हैं न कि नकद में।

- (b) केनरा बैंक, जयपुर को सुश्री क्यू द्वारा की गई सावधि जमा की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1.1.2023 को नवीनीकृत सावधि जमा के अलावा अन्य सावधि जमा का मूल्य केवल ₹7 लाख है, और इसलिए, कुल मिलाकर ₹10 लाख या उससे अधिक नहीं है वित्तीय वर्ष 2022-23.

- (c) क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या संस्थान को सुश्री के द्वारा किए गए नकद भुगतान की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। क्रेडिट कार्ड के संबंध में सी, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 1,17,900 (₹ 19,500 x 4 + ₹ 13,300 x 3) के कुल नकद भुगतान ₹ 1 लाख से अधिक हैं।

हालाँकि, अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 तक प्रत्येक माह के लिए ₹59,500 के भुगतान की सूचना ऐसे बैंक या कंपनी या संस्थान को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लेनदेन का कुल मूल्य, ₹2,97,500 है, ₹10 लाख से कम है।

- (d) श्री जेड द्वारा ₹ 2 लाख के भुगतान की सूचना मेसर्स अरोरा डिज़ाइनर्स को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री जेड से कपड़ों की बिक्री के विरुद्ध नकद भुगतान की प्राप्ति ₹ 2 लाख से अधिक नहीं है।

(ii) **प्राथमिकता का सिद्धांत**

- (a) **ग़लत** - न केवल अनुपात निर्णय (किसी मामले का निर्णय करने का औचित्य), बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का ओबिटर डिक्टा (किसी मामले का निर्णय करते समय दी गई अतिरिक्त टिप्पणियाँ, टिप्पणियाँ और राय) भी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।
- (b) **ग़लत** - जब सुप्रीम कोर्ट की समान शक्ति वाली दो पीठों के दो असंगत निर्णय होते हैं, तो बाद के समय में निर्णय मान्य होगा।
- (c) **ग़लत** - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को निचली अदालतों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हालाँकि ऐसे निर्णय प्रति इन्क्वैरियम (यानी, वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किए बिना) हैं।



(d) **ग़लत** - निचले अधिकारी ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकते जो उस उच्च न्यायालय के निर्णयों से असंगत हों जिनके अधिकार क्षेत्र में वे कार्य करते हैं, यहां तक कि मुद्दे को जीवित रखने के उद्देश्य से भी।

(b) (i) व्याख्या के सामान्य नियम का तात्पर्य है कि एक संधि की व्याख्या की जाएगी -

- सद्भाव;
- उसकी शर्तों को दिए जाने वाले सामान्य अर्थ के अनुसार; और
- संदर्भ में और इसके उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में।

(ii) पैक्टा सनट सर्वदा (अच्छे विश्वास में) का तात्पर्य है कि लागू प्रत्येक संधि-

- पार्टियों पर बाध्यकारी है; और
- उनका अच्छे विश्वास से पालन किया जाना चाहिए।

(iii) ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें एक करदाता यह विश्वास कर सकता है कि दोनों में से किसी एक या दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा किया गया व्यवहार कर संधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

ऐसे मामले में, विवाद समाधान की आवश्यकता है जिसे ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल के तहत मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 25 द्वारा संबोधित किया गया है। इस अनुच्छेद में दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों को द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होकर संघर्ष को हल करने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र मॉडल कन्वेंशन आपसी समझौते की प्रक्रिया पर लेख के लिए दो विकल्प प्रदान करता है - वैकल्पिक ए और वैकल्पिक बी। ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन के तहत, करदाता किसी भी अनुबंधित राज्य से अनुरोध कर सकता है जबकि संयुक्त राष्ट्र मॉडल (वैकल्पिक ए) करदाता को निवास राज्य या उसकी राष्ट्रीयता वाले देश में जाने पर विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र मॉडल का वैकल्पिक बी अनुच्छेद 25 पारस्परिक अनुबंध की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक मध्यस्थता प्रक्रिया के संदर्भ पर विचार करता है।